



2026:AHC:54991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 10827/2026

ब्रजेंद्र प्रताप गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता: राजीव कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह आवेदन आवेदक द्वारा समन आदेश दिनांक 05.03.2025 और एन.बी.डब्ल्यू. आदेश दिनांक 19.01.2026 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, झाँसी द्वारा शिकायत वाद संख्या 35454/2024 (मेहर प्रकाश बनाम ब्रजेंद्र प्रताप गुप्ता), धारा 138 एन.आई. एक्ट, थाना नवाबाद, जिला झाँसी के अंतर्गत पारित किए गए हैं और वर्तमान में पीठासीन अधिकारी/अतिरिक्त न्यायालय, झाँसी में लंबित हैं।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि पक्षों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि धन के भुगतान के संबंध में कुछ विवाद है, इसलिए समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय शीर्ष अदालत द्वारा दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) SCC 663 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत हैं:-

17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं /उद्धृत: अरुण मोहन, 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के विषय पर कानून सुधार की दिशा में कुछ विचार—मामलों के सैलाब से निपटना' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर/:

"...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ सजा (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक माध्यम अधिक है। शिकायतकर्ता का हित मुख्य रूप से चेक के आहर्ता को जेल में देखने के बजाय पैसा वसूलने में निहित है। जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की अवधि काटने को तैयार है, चेक धारक के लिए उपाय के रूप में बहुत कम उपलब्ध है।

यदि हम एक तरफ उन शिकायतों की संख्या की जाँच करें जिनका अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'निस्तारण' हो गया और दूसरी तरफ वे मामले जिनमें निर्णय और दोषसिद्धि की कार्यवाही आगे बढ़ी, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझ गया था और केवल बहुत कम संख्या में मामले जारी रहे।"

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक के अनादर के अपराध के संबंध में, उपाय के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा जताई गई इन आशंकाओं को भी कुछ समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निस्तारण किया जा रहा है, भले ही मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान, जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में शमन को बहुत देरी से चुनते हैं।

.....

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटॉर्नी जनरल का तर्क यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों का संज्ञान लेते ही शमन चुनने के बजाय इसे अंतिम विकल्प के रूप में चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं और समझौते का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। हालांकि इस तरह के व्यवहार को मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कठोर तथ्य यह है कि शमन चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित मामलों के बोझ में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से समझौता करने को तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन का विकल्प चुनें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास कोई वैध बचाव है जैसे कि गलती, जालसाजी या जबरदस्ती, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है। "

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर अपने प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए आवेदन दे सकता है और चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन दिए जाने पर, संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को आगे अवसर प्रदान करेगा, जो इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।
6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर मुकदमे का सामना करना होगा और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे बढ़ने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में निर्णय दिए जाने तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।
8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में धारा 528 बीएनएसएस के तहत यह आवेदन दिया गया है।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

18 मार्च, 2026

एस.के.डी.

(दीपक वर्मा, जे.)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।